वृद्धि के संबंध में एशियाई परिदृश्य : भारत के लिए संभावनाएं*

या.वे.रेड्डी

मोनिटरी अथोरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा आयोजित जी-30 के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सेमिनार में आने पर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। वस्तुतः मेरे लिए यह सम्मान और गौरव की बात है कि मैं वित्तीय विश्व के वैश्विक गुरुओं के बीच में हूं। मैं अपने विनम्र प्रस्तुतीकरण को पांच भागों में विभाजित करता हूं, वे हैं - भारतीय अर्थव्यवस्था की रुपरेखा; भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां; वैश्विक असंतुलनों का भारत पर प्रभाव; भारत की आसानी से मापी न जाने वाली कुछ शक्तियां तथा एशिया के साथ भारत के बढ़ते हुए आर्थिक संबंध।

भारतीय अर्थव्यवस्था की रुपरेखा

- भारतीय अर्थव्यवस्था 1980 के बाद से लगभग 6 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर से बढ़ रही है, और पिछले तीन वर्षों से 8 प्रतिशत से अधिक की दर से। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-2012) के लिए मसौदा दृष्टिकोण पत्र यह सुझाता है कि यह अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष 8 से 9 प्रतिशत के बीच बढ़ सकती है।
- भारत ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय ऊर्जस्विता को दर्शाया है, तथा अनेक भयंकर आघातों के प्रतिकूल संक्रामक प्रभाव से अपने आपको बचाया है।
- 1990 के बाद मध्य दशक से मुद्रास्फीति की दर निम्न और स्थिर रही है, जो 5 प्रतिशत वार्षिक की संतुलित रही है। सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक का सांझा इरादा मध्यावधि में मुद्रास्फीति की दर को 5 प्रतिशत से नीचे रखना रहा है।
- हम सकल घरेलू निवेश की दर में 2001-02 में सघउ के 23.0 प्रतिशत से 2004-05 में 30.1 प्रतिशत की दर तक निरंतर वृद्धि पाते हैं। सकल घरेलू बचत दर भी इसी अवधि में 23.6 प्रतिशत से बढ़कर 29.1 प्रतिशत हो गई है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बचत में हुई भारी वृद्धि का भी उल्लेखनीय योगदान है।
- वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात (आईसीओआर) द्वारा मापे गए अनुसार पूंजी के उपयोग की उत्पादकता एशियाई मानकों से ऊंची है और अब वह निम्नमुखी प्रवृत्ति दर्शा रही है जो उत्पादकता में वृद्धि तथा विद्यमान क्षमता के सघन उपयोग को प्रदर्शित करती है। यह अर्थव्यवस्था में निवेश के वर्तमान स्तर तथा देशी बचतों में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति को देखते हुए भविष्य में सतत उच्च वृद्धि के लिए संभावनाओं की ओर संकेत करती है।
- हाल के वर्षों में एक उल्लेखनीय गतिविधि विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर सुधार होते रहने की हुई है। इसको घरेलू और निर्यातगत मांग से समर्थन, बढ़े हुए क्षमता उपयोग, क्षमताओं में वृद्धि करने तथा निजी कारोबार और उपभोक्ता के विश्वास में सुधार से समर्थन मिला है।
- सेवा क्षेत्र का योगदान सघउ के 60 प्रतिशत बैठता है तथा यह 1990 के बाद के मध्य दशक से 9 प्रतिशत वार्षिक की गति से बढ़ रहा है। इसमें रोजगारों के सृजन तथा अतिरिक्त आय को पैदा करने की क्षमता भी है।
- 1990 के बाद के दशक के दौरान गरीबी के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 2004-05 के अंतिम सर्वेक्षण से प्रकट होता है। वृद्धि का कार्य-निष्पादन तथा भावी संभावनाएं आगे आने वाले वर्षों में प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी तथा न्यून रोजगारी से निपटने में समर्थ होंगी।
- केंद्र और राज्यों - दोनों सरकारों की राजकोषीय स्थिति राजकोषीय घाटे के संकेतकों में लक्ष्यबद्ध कमी की दृष्टि से समेकन की ओर बढ़ रही है।
- सघउ के प्रति चालू खाता घाटा भारत में संतुलित रहा है। चालू खाता पुनः मामूली-से घाटे में आने से पहले 2001-02 से 2003-04 की अवधि के दौरान अधिशेष में था। यह आशा की जाती है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8 से 9 प्रतिशत के दायरे में अनुमानित सघउ की वृद्धि दर के बीच यह 2 से 3 प्रतिशत के दायरे में बना रहेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय लगभग 165 बिलियन अमरीकी डालर का है और यह देश के कुल बाह्य ऋण से भी काफी ज्यादा है।
- मौद्रिक नीति के अंतरण प्रक्रिया-तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए वित्तीय बाजारों, विशेषकर मुद्रा, सरकारी प्रतिशत तथा विदेशी मुद्रा बाजारों का पोषण और विकास कर दिया गया है।

* मोनिटरी अथोरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा 18 सितंबर 2006 को सिंगापुर में आयोजित समूह -30 (जी-30) के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सेमिनार में डॉ.या.वे.रेड्डी, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया व्याख्यान।

- प्रतिस्पर्धा, विनियामक उपाय नीतिगत परिवेश तथा बैंकों सहित बाजार के खिलाड़ियों के बीच अभिप्रेरणा के संयुक्त प्रभाव से वित्तीय क्षेत्र ने बेहतर शक्ति, दक्षता और स्थिरता प्राप्त कर ली है।
- श्रमिक कामगारों को इधर से उधर आने जाने (सेवा में बदलाव) की पर्याप्त आजादी है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, विशेषकर संघ बनाकर जो जहां कुछ परिवर्तनों को लाना कठिन बना देते हैं, वहीं प्रतिस्पर्धा से लड़ने के लिए ऊर्जस्विता और समय पर सुधार लाने को सुनिश्चित करती है।

भारतीय वृद्धि प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए प्रमुख चुनौतियां

- पहली है - मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से भौतिक बुनियादी संरचना की खराब हालत। यहां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है - विनियामक ढांचा जिस पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। प्रौद्योगिकीय गतिविधियां, तथा देशी निर्माण क्षमताओं की तीव्रतापूर्वक वृद्धि को चाहिए कि वह तीव्र और दक्ष अनुपालन की प्रक्रिया की सहायता करे। देशी वित्तीय क्षेत्र के स्वस्थ बुनियादी तत्वों तथा विदेशी निवेशकों की बढ़ी हुई रुचि को देखते हुए इनको निधियन में कोई गंभीर समस्या नहीं आएगी। एक दूसरी चिंता है लागत वसूली। जिससे आशा की जाती है कि यह सार्वजनिक निजी सहाभागिता को बदलेगी। इन मुद्दों के मध्यावधि में सुलझ जाने की आशा के लिए आधार हैं।
- दूसरी है - राजकोषीय समेकन। केंद्र सरकार का हाल का बजट इस समेकन को रास्ते पर ले आया है। जिसमें राजस्व (चालू) घाटे को समाप्त करने के लिए 2009 तक सकल राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्यों के वित्त पर हमारे अध्ययन उनके राजकोषीय स्वास्थ्य के प्रति आशावाद को आधार प्रदान करते हैं। हम दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मानते हैं जो राजकोषीय सशक्तीकरण में परिणत हो जाएंगे। इनमे से एक है - आर्थिक सहायिका, जो उपयुक्त नहीं हैं, की समाप्ति तथा कर-छूटों, जो विकृतकारी हैं, की समाप्ति। जहां किसी राजनीतिक परिवेश में राजकोषीय समेकन कठिन है, हमारी व्यवस्था में भी ऐसा ही है, परंतु आशावाद के लिए आधार हैं।
- तीसरी - और शायद सबसे ज्यादा चुनौतीभरी कृषि के विकास से संबंधित है। जहां 60 प्रतिशत से ज्यादा श्रमिक शक्ति कृषि पर निर्भर है वहीं कृषि से उत्पन्न सघउ वृद्धि की दर जनसंख्या में वृद्धि की दर से मामूली-सी ही ज्यादा है जो गरीबी में त्वरित कमी लाना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कृषि और त्वरित वृद्धि लाने के लिए विधायी, संस्थागत तथा रवैयागत परिवर्तन सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाने के लिए जरुरी हैं। नीति निर्माताओं में इस मुद्दे पर मान्यता बढ़ती जा रही है।
- चौथी है - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को जोकि कम उद्वेगशील है, आकर्षित करने के लिए जोर देने की ओर रुझान होने की जरुरत है। इसके लिए देशी और विदेशी पूंजी के लिए आम तौर पर निवेश के परिवेश को अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।
- पांचवीं है - हमारी जनसंख्या के काफी बड़े भाग को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अनिवार्य सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी एक प्रमुख संस्थागत चुनौती है। यह पूरे मन से स्वीकार किया गया है कि शिक्षा गरीबों को वृद्धि की प्रक्रिया में भाग लेने में शक्ति संपन्न बनाएगी तथा गरीबों को न्यूनतम पैठ की दृष्टि से स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं और उपलब्धि में अंतराल को पाट देगी।
- विनिर्माण और सेवाओं में तीव्र वृद्धि के चलते, एक अचानक और सघन दबाव शहरी बुनियादी संरचना तथा शहरी सेवाओं की उपलब्धि और गुणवत्ता के संबंध में बन गया है। राष्ट्रीय ''शहरी नवीकरण मिशन'' के चालू किए जाने के बाद से इस दिशा में उल्लेखनीय शुरुआत कर दी गई है।

भारत के लिए वैश्विक असंतुलनों के निहितार्थ

- भारत ने भारी चालू खाता अधिशेषों और भारी चालू खाता घाटों की दृष्टि से वैश्विक असंतुलनों में न तो सकारात्मक रुप से और न ही नकारात्मक रुप से कोई बड़ा योगदान किया है; बचत और निवेश कमोबेश संतुलित रहे हैं; अर्थव्यवस्था घरेलू मांग से प्रेरित है, और सामान्यतया हमारी नीतियां, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों सहित, बाजारोन्मुखी हैं। इस प्रकार भारत ऐसी नीतियों का अनुसरण कर रहा है जिन्होंने न केवल इसकी भलीभांति सेवा की है, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी योगदान किया है।
- प्रमुख मुद्राओं में या संबंधित ब्याज दरों या व्यापार सहभागियों के चालू खातों में कोई भारी और तीव्र समायोजन किए जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, हालांकि यह प्रभाव अन्य अनेक उदीयमान बाजारी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़नेवाले प्रभावों की तुलना में कम होगा।
- भारत अपने राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों पर निर्भर नहीं है और इसलिए वैश्विक गतिविधियों के कुछ प्रतिकूल परिणाम शांत हो जाते हैं तथापि, वैश्विक गतिविधियों का छुटपुट प्रभाव घरेलू ब्याज दरों पर होगा और इस प्रकार राजकोषीय स्थिति पर भी।
- वैश्विक असंतुलनों पर कोई आकस्मिक समायोजन भारत में कंपनियों, बैंकों और परिवारों पर हो सकता है, हालांकि उनका जोखिम /अनुभव, सकल रुप में, बाह्य क्षेत्र में अधिक नहीं है। कंपनियों पर प्रभाव की दृष्टि से यदि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निवेशकों के विश्वास में किसी

बदलाव के फलस्वरुप उसकी व्याप्ति में प्रसार होता है तो, वे कंपनियां जिन्होंने अर्थक्षम दरों पर राशियां उधार ली हैं, संभवतः ज्यादा प्रभावित होंगी बनिस्बत उनके जिन्होंने निश्चित दर पर ऋण लिए हैं।

- हालांकि जोखिम पूर्ण आस्तियों में बैंकों के ऋण/निवेश को रिज़र्व बैंक के विनियामक कार्रवाई द्वारा कठोरतापूर्वक सीमित रखा गया है, फिर भी यदि पूंजी के आगमों का प्रत्यावर्तन शुरू हो गया तो आस्ति मूल्यों में गिरावट आ सकती है। पुनः भारत में बैंकों ने सरकारी ऋण तथा अन्य निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में काफी निवेश किया हुआ है, अतः यदि अंतरराष्ट्रीय ब्याज की दरें घरेलू ब्याज की दरों को प्रभावित करती हैं तो बैंकों को अपने निवेश संविभाग का अवमूल्यन नहीं करना पड़ेगा, तथापि बैंकिंग क्षेत्र ने इस प्रकार के संभावित आघातों को खपाने की अतिरिक्त शक्ति प्राप्त कर ली है, विशेषकर विनियामक कार्रवाइयों द्वारा उसे इसमें सहायता मिली है।
- जहां तक परिवारों पर प्रभाव पड़ने का संबंध है, एक जोखिम है कि सामान्यतः ब्याज दरों में वृद्धि आवासीय बाजार को प्रभावित कर सकती है तथा परिवारों के तुलनपत्रों में ब्याज दरों के जोखिम को दर्शाएगा। इससे बैंकों के लिए ऋणों की हानियों का खतरा बढ़ जाता है। बैंकिंग क्षेत्र का आवासीय ऋणों में समग्र शेयर /निवेश /ऋण अपेक्षाकृत अल्प है, अतः प्रतिकूल प्रभावों का बैंकिंग क्षेत्र पर सर्वांगी प्रभाव नहीं होगा।

आसानी से मापी न जा सकने वाली शक्तियां

- पहली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्नातकों का भारी समूह, तथा लाखों / करोड़ों लोग, जो अंग्रेजी भाषा से परिचित हैं, अब तक उभरते भारत के लिए शक्ति के स्रोत रहे हैं। बहु भाषाओं से परिचय भारत में लोगों को बहु संस्कृति वाली स्थितियों को बेहतर रुप में अपनाने में समर्थ बनाता है, यह उनके लिए आसान बना देता है कि वे अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों में सुचारू रुप से समायोजित हो जाते हैं। इस जरुरत की भी मान्यता बढ़ी है कि अनुसंधान और दक्षताओं/ कौशलों की गुणवत्ता को बनाया और बढ़ाया जाए।
- दूसरी, अपने अधिकारों की रक्षा करने तथा बेहतर आत्मसम्मान प्राप्त करने में सहायता करने तथा अपने वैयक्तिक जीवन और सामाजिक संबंधों पर नियंत्रण करने के लिए कई राज्यों द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए की गई पहलें प्रभावी हैं।
- तीसरी, मुक्त प्रेस की विद्यमानता ज्यादतियों के विरुद्ध कुछ आश्वासन प्रदान करती है, तथा वह सरकारों को सभी स्तरों पर किसी अन्य प्रकार की तुलना में अधिक जबाबदेह बनाती है। हाल ही में बने सूचना का अधिकार अधिनियम ने सार्वजनिक नीतियों में पारदर्शिता की विश्वसनीयता को बढ़ाने में योगदान किया है। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र और मीडिया हमारे राष्ट्र के लिए सक्रिय और महत्वपूर्ण है।
- चौथी, मिली-जुली सरकारों और केंद्र और कई राज्यों दोनों स्तरों पर आवधिक रुप से हुए चुनावों के बावजूद राजनैतिक परिवेश को राजनैतिक प्रणाली की स्थिरता का नाम दिया जा सकता है। जैसा कि जोन हॉपकिन्स विश्व विद्यालय वाशिंगटन के लोक तंत्र विशेषज्ञ माइकल मैडलबम ने कहा है,

  ''भारतीय लोकतंत्र की सतह पर अनेक उद्वेलन हैं, परंतु भारतीय राजनैतिक प्रणाली के गहरे तल में भारी सहमति है।''
- पांचवीं, भारत अगले कुछ दशकों में विश्व में सबसे युवा देशों में से एक होगा। यह ''जनसंख्यागत लाभांश'' अनिवार्य लाभ के रुप में दिखाई देता है, बशर्ते इसे प्राप्त करने के लिए कौशल उन्नयन, तथा सुदृढ़ बेहतर संचालन की पूर्व शर्तें पूरी कर दी जाएं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह जनसंख्यागत अंतरण लंबी अवधि तक चलेगा क्योंकि भारत में राज्य केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस अंतरण के विभिन्न स्तरों पर हैं।
- छठीं, बेहतर स्थिति भारत की कारोबारी संस्कृति की है। कारोबारी परिवेश की दृष्टि से, बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ प्रभावपूर्ण वृद्धि एक उन्नयनकारक अभ्यास रहा है, जिसमें व्यापक आधारवाले उद्यमियों का बढ़ता हुआ वर्ग है। ये प्रवृत्तियां शायद भारत में व्यावसायिकता से सराबोर तथा वैश्विक रुप से प्रतिस्पर्धी बनने की भावना के साथ-साथ बढ़ते हुए उद्यमी वर्ग के बीच नवोन्मेष के लिए ललक में दिखाई पड़ती हैं।
- सातवीं, प्रादेशिक सरकारों के बीच विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बढ़ता हुआ उत्साह है, अतः हम यह आशा कर सकते हैं कि वे भौतिक बुनियादी संरचना और बेहतर कंपनी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लालायित होंगे।

मैं अपनी बात फाइनेंसियल टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े श्री एडवार्ड ल्यूस ने अपनी नवीनतम पुस्तक ''इन्सपाइट ऑफ दि गाड्स दि राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया'' में भारत के बारे में जो कहा है उसे दोहराते हुए पूर्ण करना चाहूंगा -

''भारत के पास महानता तक ले जाने वाला ऑटोपाइलट नहीं है, परंतु यह एक अक्षम पाइलेट को लेकर चलेगा भलेही वह प्लेन को क्रश कर दे।''

एशिया के साथ आर्थिक संबंध

- चीन और भारत न केवल कम कीमतवाला माल और सेवाएं उत्पन्न करके वैश्विक अर्थव्यवस्था की मदद कर रहे हैं, बल्कि अपने संदर्भ में बाजारों का तेजी से विकास भी कर रहे हैं, जिनमें सारे विश्व में उत्पादित उपभोक्ता और पूंजीगत माल के लिए भारी मांग है। एशियाई क्षेत्र में बढ़ती हुई समृद्धि और विकासशील देशों के बीच बढ़ते हुए

व्यापार के संदर्भ में, भारत के व्यापार संबंध में एक महत्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तन आया है। आम तौर पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ और विशेषकर एशिया के साथ, जो भारत के वणिक व्यापार का बहुत बड़ा भाग बनाता है। तेल से इतर आयातों की दृष्टि से चीन हमारे लिए सबसे बढ़ा व्यापारिक भागीदार हो गया है।

- तेल आयातों को छोड़कर भारत के विदेश व्यापार का लगभग आधा एशिया के साथ होता है और वह बढ़ रहा है। 2005-06 के दौरान भारत के कुल निर्यातों में से 46 प्रतिशत निर्यात एशिया को होता है, जबकि तेल से इतर आयातों का लगभग 45 प्रतिशत आयात एशिया से आता है। अमरीका और यूएई के बाद चीन तीसरा प्रमुख निर्यात गंतव्य देश के रुप में उभरा है। एशिया के साथ भारत का कुल व्यापार (वणिक निर्यात तथा तेल से इतर आयात) 2000-01 के 29 बिलि.अम. डालर की तुलना में 2005-06 में 91.5 बिलियन अमरीकी डालर के हो गए जिसमें 47.2 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात और 44.3 बिलियन अमरीकी डालर का तेलेतर आयात शामिल है।
- एशियान के साथ कुल व्यापार (निर्यात + तेलेतर आयात) कई गुना बढ़ा है और वह 2000-01 के 6.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2005-06 में 21.1 बिलियन अमरीकी उालर का हो गया है। 2005-06 के दौरान एशियान क्षेत्र को भारत के निर्यात 10.5 बिलियन अमरीकी डालर के और आयात 10.6 बिलियन अमरीकी डालर के हो गए हैं।
- भारत एशियान का औपचारिक वार्ता का भागीदार हो गया है और दक्षिण-पूर्व एशियान और एशिया में फैले संस्थाओं के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने का इच्छुक है। इसी प्रकार, सार्क देशों के साथ भारत के व्यापार को जो वर्तमान में 6.7 बिलियन अमरीकी डालर के आसपास है, और आगे बढ़ने की भारी संभावनाएं हैं।
- क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने की दृष्टि से भारत, चीन, जापान, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मालद्वीपःभूटान, बंगला देश, नेपाल, श्रीलंका और एशियान जैसे क्षेत्रीय ब्लाकों सहित कई देशों के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग, करार /व्यापार करार किए हैं।
- श्री रेमांड लिम.सिंगापुर के परिवहन मंत्री तथा विदेश कार्यों के द्वितीय मंत्री ने अपने लेख ''क्रीएटिंग ग्लोबल कनेक्टेड एशियन कम्युनिटी', जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्त और विकास के जून 2006 के अंक में प्रकाशित हुआ था, लिखा था -

''चीन और भारत का अभ्युदय श्रम और व्यापार के क्षेत्रीय प्रभागों की पुनर्व्याख्या करेगा और दक्षिण-पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को एक नई और उच्चतर वृद्धि पथ पर ले जाने में सहायता करेगा। चीन और भारत एशिया को विश्व अर्थव्यवस्था के केंद्र में ले आएंगे। चीन और भारत का अभ्युदय एशिया को न केवल बढ़ने में, वरन् और अधिक समन्वित होने में सहायता कर रहा है।''